

हिन्दी



कहीं ऑनलाइन खरीदा मोबाइल चोरी का तो नहीं?

विनीत खरे

बीबीसी संवाददाता, दिल्ली से

🕒 9 अक्टूबर 2015

साझा कीजिए



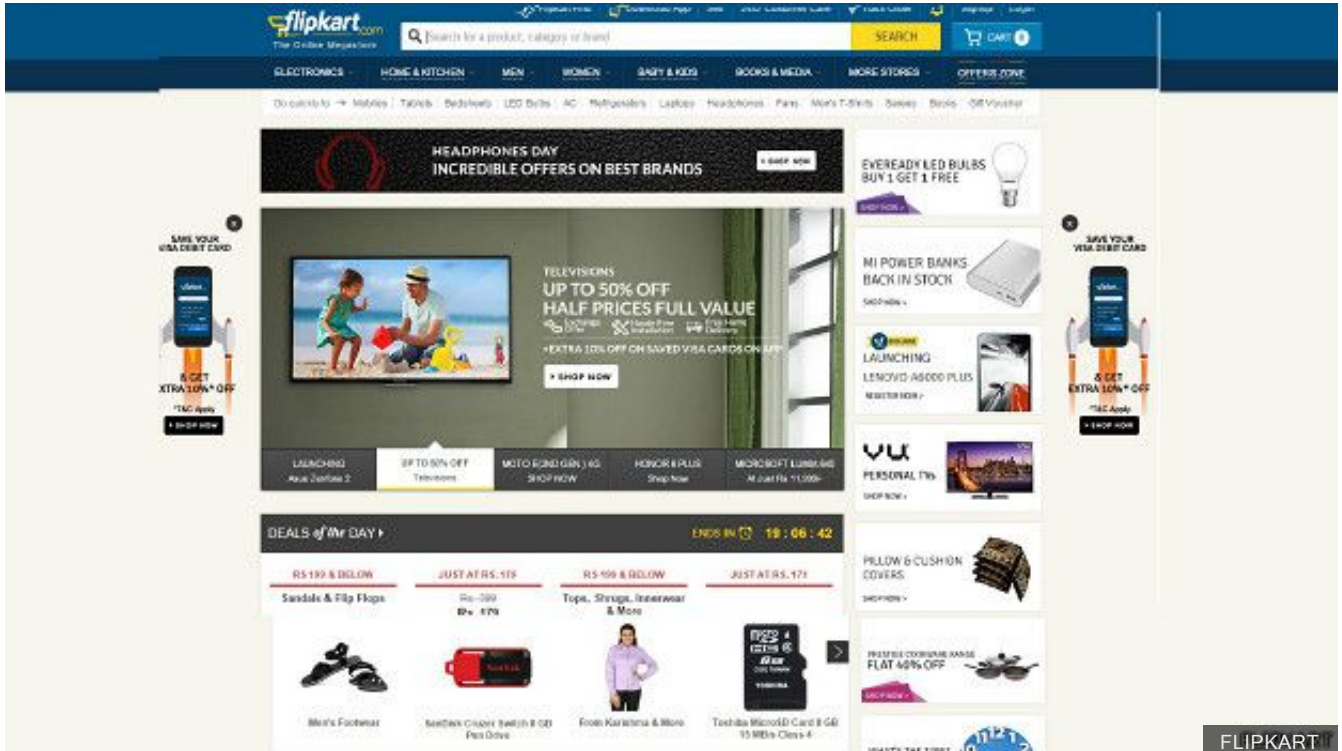
अगर आपको पता चले कि आपने जो महंगा मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन खरीदा है, वो चोरी का है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

जुलाई में दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग एक करोड़ रुपए के 600 महंगे मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए थे.

ये फ़ोन हांगकांग से भारत मंगाए गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, छानबीन पर पता चला कि चोरी हुए करीब 200 मोबाइल फ़ोन कथित तौर पर फ़्लिपकार्ट डॉट कॉम पर देश के कई हिस्सों में बेच दिए गए थे.

इस मामले में छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और जांच जारी है लेकिन उन लोगों की क्या ग़लती जिन्होंने ये फ़ोन कंपनी वेबसाइट पर खरीदे?

पढ़ें, विस्तार से



ई-कॉमर्स की मदद से देश के एक कोने में बैठा विक्रेता दूसरे कोने में उपभोक्ता को सामान बेच पा रहा है. ऐसे वक़्त जब बड़ी संख्या में घर के राशन से लेकर गाड़ियां तक ऑनलाइन खरीदी जा रही हैं, ये ताज़ा पुलिस जांच कई सवाल खड़े करती है.

बीबीसी को भेजे एक वक्तव्य में फ़्लिपकार्ट ने कहा, कंपनी के 40,000 से ज़्यादा विक्रेता कड़े दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं और दिशानिर्देशों की अवहेलना को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है.

कंपनी का कहना है कि उसकी टीम समय-समय पर विक्रेताओं की जांच करती रही हैं और नकली सामान बेचने वाले कई विक्रेताओं को ऐसा करने से रोका जा चुका है.

कंपनी ने कहा कि नकली, चोरी का सामान बेचने वालों या कानून का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

कंपनियों पर दबाव

साइबर मीडिया के समूह संपादक इब्राहिम अहमद बताते हैं, "ये सब नई कंपनियां पिछले दो-तीन सालों में उभरी हैं. इनके यहां प्रणालियों को मजबूत करने में वक्त लगेगा. ई-कॉमर्स कंपनियों में होड़ लगी हुई है. कंपनियों की सफलता इस बात से है कि उनके कितने आपूर्तिकर्ताओं से टाई-अप हैं."



Thinkstock

उनके मुताबिक, इन कंपनियों ने नियम तो बना रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां इसका पालन नहीं करतीं.

वो कहते हैं, "बड़ी कंपनियां विदेशी निवेशकों के पैसों से चल रही हैं और उन पर अच्छे नतीजे दिखाने का बहुत दबाव रहता है."

साइबर मामलों के जानकार पवन दुग्गल कहते हैं, "बहुत से मामलों में ऑनलाइन विक्रेता पूरा बिल नहीं देते या वादा तो करते हैं लेकिन बिल नहीं भेजते. कई ध्यान भी नहीं देते हैं. लेकिन उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है."

उधर, डीसीपी (इंदिरा गांधी हवाई अड्डा) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से जो जानकारीयां मांगी हैं वो उन्हें दी जा रही हैं और कंपनी जांच में सहयोग कर रही है.

बड़ा बाज़ार

ऑडिट कंपनी प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स के तकनीक और ई-कॉमर्स प्रमुख संदीप लड्डा के अनुसार, भारतीय ई-कॉमर्स बाज़ार एक लाख 25 हजार करोड़ का है और पिछले पांच सालों से इसमें 36 प्रतिशत कंपाउंडेड वार्षिक प्रगति दर की रफ़्तार से बढ़ोतरी हो रही है.

क्या कंपनियां सावधानियां बरत रही हैं? क्या उनके लिए ऐसा करना संभव भी है? उनका क्या अनुभव है?



AP

संदीप लड्डा बताते हैं, “हर कंपनी तो नहीं लेकिन बड़ी कंपनियां सख्त जांच करती हैं. पीडब्ल्यूसी जैसी कंपनियां विक्रेताओं की जांच करने में ई-कॉमर्स कंपनियों की मदद करती हैं, लेकिन इस व्यवस्था को 100 प्रतिशत फुलप्रूफ बनाना संभव नहीं है.”

उधर फ़्लिपकार्ट के वक्तव्य के अनुसार, “विक्रेता के लिए हमारे पास तीन श्रेणी का रेटिंग सिस्टम है. विक्रेता की रेटिंग ग्राहक की रेटिंग, खरीदारी रद्द करने जैसी चीज़ों पर निर्भर रहती है.”

कंपनी का कहना है कि विक्रेताओं को सिर्फ़ असली वॉरंटी वाले मौलिक उत्पाद बेचने की इजाज़त होती है और जिन विक्रेताओं को दूसरी कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर देती हैं, वो फ़्लिपकार्ट पर सामान नहीं बेच सकतीं.

क्या करें उपभोक्ता

विक्रेता का रिव्यू देखें. पढ़ें लोग विक्रेता से कितने संतुष्ट हैं.

उत्पाद की तस्वीर ध्यान से देखें.

पता करें कि उत्पाद नया है या पुराना.

उत्पाद के बारे में कितने विस्तार से जानकारी दी गई है.

सुरक्षित वेबसाइट पर सामान खरीदें.

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल साइबर कैफ़े में न करें.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉइड ऐप के लिए यहां [क्लिक](#) करें. आप हमें [फ़ेसबुक](#) और [ट्विटर](#) पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)

इस खबर को शेयर करें

शेयरिंग के बारे में



सबसे ऊपर चलें

संबंधित समाचार

मोबाइल, टीवी, कार से भी हैकिंग का खतरा

11 अगस्त 2015

साइबर धमकियों पर क्यों नहीं होती कार्रवाई?

12 जुलाई 2015

ऑनलाइन शॉपिंग सावधानी से करें

8 जुलाई 2015

कड़क पासवर्ड बनाने के कुछ नुस्खे

27 जुलाई 2015

अधिक भारत की खबरें >**भारतीय मीडिया कितना निष्पक्ष है?**

⌚ 3 घंटे पहले



दंगों को तीन साल, मगर बदले नहीं हालात

⌚ 5 घंटे पहले



'जेएनयू में हिन्दुत्ववादी विचारों पर बैन रहा है'

⌚ 3 घंटे पहले

टॉप स्टोरी

देश के खिलाफ नारे लगाना देशद्रोह है या नहीं?

पिछले न्यायिक फैसलों पर मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने एक पक्ष रखा है और दूसरा पक्ष रखा है बीजेपी के अमिताभ सिन्हा ने.

🕒 51 मिनट पहले

कार्ड की ज़रूरत नहीं, फ़ोन से पैसे का लेन-देन

🕒 2 घंटे पहले

'जेएनयू में हिन्दुत्ववादी विचारों पर बैन रहा है'

🕒 49 मिनट पहले

विज्ञापन

See the flight.
See the price.
See you soon.

Replay

Fly to
Europe

from

48,900*

→ Book now



Lufthansa

* Sales Period: 09 Feb to 29 Feb 2016. Travel Period: 9th Feb to 15th May 2016. T&C apply.

ज़रूर पढ़ें



मुंबई में हैं ईसा पूर्व की 7 गुफाएं



गोलीबारी के बीच चलता स्कूल



रामायण परीक्षा में फ़ातिमा अक्वल



'खुद मियां फ़ज़ीहत, औरों को..'



अमरीका को क्या बनाना चाहेंगे ट्रंप?



खुद को श्रद्धांजलि देने पहुंची



'करोड़ों की कार हज़ारों में लें'



'मज़दूरों के वेतन से बने हथियार'



देवबंदी-बरेलवी आमने सामने

सबसे लोकप्रिय

- | | |
|--|----|
| देश के खिलाफ नारे लगाना देशद्रोह है या नहीं? | 1 |
| कार्ड की ज़रूरत नहीं, फ़ोन से होगा पैसे का लेन-देन | 2 |
| भारतीय मीडिया कितना निष्पक्ष है? | 3 |
| मुंबई में मिलीं ईसा पूर्व की 7 गुफाएं | 4 |
| 'जेएनयू में हिन्दुत्ववादी विचारों पर बैन रहा है' | 5 |
| 'संदेश स्पष्ट- जो रास्ते में आएगा, पीटा जाएगा' | 6 |
| 60 सेकंड की कसरत कीजिए, फ़िट रहिए | 7 |
| 'गरीब का बेटा है, इसलिए फंसाया गया है' | 8 |
| अमरीका को क्या बनाना चाहते हैं ट्रंप? | 9 |
| दंगों को तीन साल, मगर बदले नहीं हालात | 10 |

गूगल के विज्ञापन

British Expat In India?

£70k+ In UK Pensions? Download A Free Expat Guide & Expert Advice!
your.expatspensionreview.com

Play & Win Cash Online

Rummy is a Traditional Indian Game Start Playing & Win Cash Prizes!
www.ace2three.com/Play-Rummy

Apply Credit Card Online

Credit Cards for all salaries Credit Cards with Unlimited Rewards
bankbazaar.com/Apply_Credit_Card

बीबीसी

[News](#)[Sport](#)[Weather](#)[Radio](#)[इस्तेमाल की शर्तें](#)[बीबीसी के बारे में](#)[गोपनीयता की नीति](#)[Cookies](#)[Accessibility Help](#)[Parental Guidance](#)[बीबीसी से संपर्क](#)[हमारे साथ विज्ञापन करें](#)[विज्ञापनों के विकल्प](#)

Copyright © 2016 बीबीसी. बीबीसी बाहरी साइटों पर मौजूद सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. [एक्सटर्नल लिंक्स पर बीबीसी की नीति](#)